P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-VJanuary-2015
E: ISSN NO.: 2349-980X

ग्रामीण विकासः जनसहभागिता और स्वच्छ भारत अभियान

बीरपाल सिंह ठैनुआं
सीनियर असिस्टेण्ट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग,
डी. ई. आई. (डीम्ड यूनिवरसिटी),
दयालबाग, आगरा

सारांश

भूमण्डलीकरण के दौर में जहाॅ एक ओर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो चुकी है, अर्थव्यवस्था के द्वारा दुनिया के देशों क उद्यमियों के खोल दिये गये हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठवी सबसे बडी अर्थव्यवस्था है, विदेशी मुद्रा भण्डार जो एक समय 3 अरब डॉलर था आज वही 338 अरब डॉलर से अधिक है। वहीं दूसरी ओर गाँव में रहने वाली जनसंख्या को उसी के भाग्य पर नहीं छोडा जा सकता। आज भी भारत में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में ही निवास करती है, कृषि क्षेत्र भारत की 50 प्रतिशत आबादी को रोजगार प्रदान करता है, कृषि क्षेत्र की जी डी पी में 14 प्रतिशत हिस्सेदारी है। गाँवों में आज भी बिजली, पानी, सडक, शौचालय, आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अतः ग्रामीण विकास समय की आवश्यकता है। यह विकास जनसहभागिता और स्वच्छ भारत अभियान से भी प्रारम्भ किया जा सकता है।

मुख्य शब्दः ग्रामीण विकास, जनसहभागिता, स्वच्छ भारत अभियान, भूमण्डलीकरण, आदर्श गांव, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बहुआयामी, आधारभूत संरचना।

परिचय

ग्रामीण विकास शब्द का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र रूप में विकास है, जिसमें ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। इस दृष्टि से ग्रामीण विकास एक व्यापक एवं बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें कृषि एवं संबन्धित क्रियाकलाप, ग्रामीण उद्योग, सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना, सामुदायिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ तथा मानव संसाधन सम्मिलित हैं। ग्रामीण विकास की अवधारणा को एक प्रक्रिया, एक प्रघटना, एक रणनीति तथा एक अनुशासन के रूप में जाना जा सकता है। ग्रामीण विकास के निम्न लिखित तत्व हैं– अ. जीवन की आधारभूत आवश्यकताएँ: जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, प्रारम्भिक साक्षरता, प्राथमिक स्वास्थ्य, जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा आदि। ब. आत्म सम्मान जैसे प्रत्येक व्यक्ति एवं राष्ट्र थोड़े बहुत आत्म सम्मान, गौरव व गरिमा को प्राप्त करता है। स. स्वतन्त्रताः जैसे स्वतन्त्रता में राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं की स्वतन्त्रता सम्मिलित है।

ग्रामीण विकास की आवश्यकता

भारत सामाजिक जीवन के प्रारम्भिक समय से ही और आज भी ग्रामीण समुदाय की भूमि है और भविष्य में भी रहेगी (सिंह 2009)। भारतवर्ष के सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में ग्रामिनी शब्द का उल्लेख है। जिसका आशय ग्राम का मुखिया आदि से है। अतः वैदिक कालीन सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। सन् 1901 में यहां 89 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती थी, जो 1951 में 83 प्रतिशत, 1971 में 80 प्रतिशत, 2001 में भी 72 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। सन् 2007 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में ग्रामीण क्षेत्र का 18 प्रतिशत योगदान था (सिह 2009)। वर्तमान समय में भी ग्रामीण क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 69 प्रतिशत भाग निवास करता है (अग्रवाल 2014)। इस समय देश में लगभग 2 लाख 25 हजार ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 6 हजार पंचायत समितियां/क्षेत्र पंचायतें और 600 से अधिक जिला पंचायतें हैं। इनमें 30 लाख चुने हुए प्रतिनिधि विभिन्न पदों पर आसीन हैं (महीपाल 2014)। आज भी भारतीय समाज में ग्रामों की उसकी श्रम शक्ति की व उसके विकास की अवहेलना नहीं की जा सकती। अतः आवश्यकता 69 प्रतिशत भारतीय मानव संसाधन के श्रेष्ठ उपयोग कर ग्रामों के विकास की है। भारतीय मानव शक्ति के महत्व को गाँधी जी ने भी स्वीकार किया था। उनके अनुसार कोई भी योजना जो केवल कच्चे माल के दोहन की है तथा वह वृहद मानव श्रम शक्ति का नकारती है वह कभी भी मानव समता स्थापित नहीं कर सकती।

वास्तविक योजना तो भारत की मानव शक्ति की श्रेष्ठ उपयोगिता में है (गाँधी 1964)।

जनसहभागिता और स्वच्छ भारत अभियान

स्वतन्त्रता से पूर्व से ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ग्रामीण पुर्ननिर्माण, ग्रामीण उत्थान तथा ग्रामीण विकास को प्रमुख स्थान दिया। स्वतन्त्रता के पश्चात से ही जमींदारी उन्मूलन, भूदान, ग्रामदान, सहकारिता, श्रमदान, ग्राम पंचायतों की पुर्नस्थापना, गाँधी ग्राम, अम्बेदकर ग्राम, लोहिया ग्राम, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजनायें चलायी गयी/चलाई जा रहीं हैं। इनमें से कुछ योजनाएं ग्रामीण विकास में अधिकाधिक सहभागिता बढाकर ग्रामीणों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्थानीय संसाधनों का उचित शोधन कर समुदाय का विकास करने के लिए चलायी गयी तो कुछ सरकारी योजना मात्र के रूप में। लेकिन इन योजनाओं के बाबजूद भी ग्रामीण विकास की जो आशा की गयी थी वह विकास प्राप्त नही हो सका। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी सहित सभी राष्ट्रीय नेता एवं नीति निर्माता इस बात को ठीक प्रकार से समझते थे कि ग्रामीण विकास के बिना भारत का विकास सम्भव नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व तथा ग्रामीण जीवन के पुर्ननिर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए 4 अप्रैल 1936 को महात्मा गाँधी ने अपने पत्र हरिजन में लिखा– भारत नगरों में नहीं बल्कि इसके सात लाख ग्रामों में निवास करता है। लेकिन हम नगरों के निवासी यह विश्वास करते हैं कि भारत नगरों में है तथा ग्राम नगरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैदा किये गये हैं। 29 अगस्त 1936 में फिर लिखा कि मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि गाँव खुशहाल होंगे तो भारत भी खुशहाल होगा (सिंह 2009)।

महात्मा गाँधी ने जिस आदर्श गांव की कल्पना की थी वह गांव पूरी तरह भारतीय पृष्ठभूमि में विकसित एवं खुशहाल गाँव था। गाँधी के शब्दों में मेरे इस आदर्श गांव में योग्य मानव निवास करेंगे। वे पशुओं की भांति अंधकार व गंदगी में नही रहेंगे। स्त्री पुरुष स्वतन्त्र होंगे तथा विश्व में किसी से भी सामना कर सकेंगे। आगे गाँधी जी लिखते हैं कि मैं जानता हूँ कि ग्रामों को आदर्श बनाना उतना ही कठिन है जितना कि भारत को आदर्श बनाना ... लेकिन यदि कोई एक आदर्श ग्राम की रचना कर सकता है तो वह सारे देश के लिए ही प्रतिमान प्रस्तुत नहीं करेगा वरन् सारे संसार के लिए ऐसा करेगा (गाँधी 1962)। इस आदर्श गांव की अवधारणा में भारत की 85 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के लिए एक आदर्श समुदाय की रचना करने का सपना था।

महात्मा गाँधी के ग्रामीण विकास के इसी सपने को साकार करने तथा भारत की दो तिहाई से अधिक जनसंख्या के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने हेतु भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता अभियान व सांसद आदर्श ग्राम योजनाएं नामक दो महत्व पूर्ण योजनाएं प्रारम्भ की हैं। ये दोनों ही योजनाएं जनसहभागिता पर आधारित हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का आधारभूत विकास जैसे बिजली, पानी, सडक, शिक्षा, नाली, कृषि, चिकित्सा आदि सुविधाओं का विकास करना ही नहीं है बल्कि जनसहभागिता के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण जनता को प्रोत्साहित करना भी है। स्वच्छ भारत अभियान पूर्णतः जनसहभागिता पर आधारित है। गाँधी जी ने भी इस संबन्ध में तत्कालीन कॉग्रेस से सदस्यों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि कॉग्रेस के अधिकांश सदस्य गाँवों से हैं, तो उन्हें गांवों की स्वच्छता के लिए दुनिया के सामने आदर्श मॉडल बनना चाहिए (गाँधी 1964)। आज भी हमारे भारतीय ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। शौचालय जैसी सुविधाएं गावों से दूर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामों में केवल 32.7 प्रतिशत घरों में शौचालय हैं (जनगणना 2011)। यह स्थिति हमारे नगरों में भी ज्यादा अच्छी नहीं है। एक सर्वेक्षण के अनुसार नगरों में एक तिहाई जनसंख्या खुले में शौच करती है। देश में 95 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन तो हैं लेकिन शौचालय का उपयोग करने वाले महज 40 करोड हैं। देश की आधे से अधिक आबादी घोर गंदगी या प्रदूषित स्थानों पर जीवन बसर करने के लिए मजबूर है (आर्येन्दु 2015)। स्वच्छता के महत्व को स्वीकार करते हुए गाँधी ने अपने आदर्श ग्राम की अवधारणा में इसे प्रमुख स्थान दिया। मेरा आदर्श ग्राम योग्य मनुष्यों से युक्त होगा। वे पशुओं की भांति गंदगी और अंधेरे में नहीं रहेंगे।... वहाँ न तो प्लेग होगा और न ही हैजा, न चिकिनपॉक्स होगा, कोई भी आलसी नहीं होगा और किसी को भी भोग विलास की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से का शारीरिक श्रम कर अपना योगदान देगा (गाँधी 1964)।

गाँधी जी के इस विचार के 80 वर्ष पश्चात भी इस तथ्य की सत्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी विकास की कल्पना नहीं की सकती। लेकिन दुर्भाग्य से हम विकास कार्यक्रमों को सरकारी कार्यक्रम मानकर उसे सरकारी कहने लगते हैं। बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में गठित ग्रामोद्धार समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में इस तथ्य को स्वीकार किया था कि ग्राम पंचायतें ग्राम विकास के अपने लक्ष्य को जनसहभागिता के अभाव में प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। ग्रामीण विकास के लक्ष्य को जनसहभागिता के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विनोवा भावे, जयप्रकाश नरायन, राम मनोहर लोहिया ने जनसहभागित के द्वारा ग्रमीण विकास को गति प्रदान की। ग्रामीण विकास के लिए गाँधी जी ने श्रम के महत्व को स्वीकार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वावलम्बन, विकेन्द्रीकरण, खादी ग्रामाद्योग पर वल दिया। गाँधी के शब्दों में एक व्यक्ति जो शारीरिक श्रम नहीं करता उसको खाने का अधिकार कैसे हो सकता है। ईश्वर ने मनुष्य को शारीरिक श्रम द्वारा मेहनत कर खाने के लिए बनाया है, जो बिना कार्य किये खाते हैं वे चोर हैं। पसीना बहाकर रोटी कमाओ, ऐसा बाइविल कहता है (गांधी 1962)।

यदि भारत के विकास में पंख लगाने है तो ग्रामों को भी भारत की विकास यात्रा में साथ लेकर चलना होगा।[6] लाख ग्रामों के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना नही की जा सकती। ग्रामीण विकास के लिए ग्रामों की स्वच्छता अति आवश्यक है। माननीय नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान के माध्यम से ग्रामीण विकास में पंख लगाकर भारत के विकास को गति प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने स्वयं अपने आदर्श

ग्राम की स्थापना में ग्रामीण स्वच्छता को आवश्यक माना। उनके अनुसार एक आदर्श ग्राम का निर्माण पूर्ण स्वच्छता से होगा। घरों का निर्माण पांच किलोमीटर की परिधि से ही लायी गयी निर्माण सामग्री से पर्याप्त प्रकाश युक्त तथा हवादार होगा। घरों के बाहर घरेलू प्रयोग हेतु सब्जी उगाने व पालतू पशुओं के लिए पर्याप्त स्थान होगा। ग्राम की गलियां सभी प्रकार की धूल से मुक्त होंगी (गाँधी 1964)। गाँधी के लिए स्वच्छता ईश्वर से एक कदम बढकर है (माटाऊछ 2014)। ग्रामों में स्वच्छता अभियान में शौचालयों का निर्माण अर्थात प्रत्येक घर में शौचालय का होना व उनका व्यवस्थित प्रयोग, पानी निकासी की उचित व्यवस्था, गोबर के ऊपलों के स्थान पर धुंआ रहित चूल्हों का प्रयोग (एल पी जी), कचरा प्रबन्धन, स्कूल व पंचायत घर की साफ सफाई, तालाबों व कुओं का रख रखाव आदि सम्मिलित हैं। इन क्रिया कलापों में ग्रामीण जन सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस जन सहभागिता को बढाने हेतु ग्राम पंयाचतों एवं ग्राम सभाओं की अहम भूमिका होगी। ग्राम पंचायतें सभी ग्रामीणों, चाहे वे गरीब हों, महिला हों, सीमान्त वर्ग से हों, को समान अवसर प्रदान करती हैं। इस संबन्ध में यह कथन महत्व पूर्ण है कि ग्राम सभाओं को जिम्मेदारी तथा पारदर्शिता के साथ और अधिक शक्तियाँ प्रदान करके जन सहभागिता तथा संशक्तिकरण में वृद्धि की जा सकेगी (मोहन्ति 2009)।

जन सहभागिता का मंत्र ग्रामीण समाज को स्वच्छता के माध्यम से विकास की धारा को आगे बढ़ाने में ही कारगर साबित ही नहीं होगा वल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए भी मील का पत्थर सावित हो सकता है, लेकिन इस तथ्य की ओर भी सजग रहने की आवश्यकता है कि यह केवल केन्द्र सरकार की एक योजना या पहल अथवा अभियान बनकर न रह जाये। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी का संदेश कोई नई बात नहीं है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 2013 से 2022 तक के दौरान ग्रामीण स्वच्छता और साफ सफाई की नीति तैयार की है। भारत सरकार ने 2019 तक भारत को खुले के शौच से मुक्त कराने के लिए एक कार्य योजना बनाई है, इस योजना के तहत देश को गन्दगी से मुक्त कराना है। इसी वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वी जयन्ती है इस दृष्टि से इस योजना का महत्व और बढ जाता है। यदि यह खुले में शौच से मुक्ति की योजना सफल हो जाती है तो यह गाँधी के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रृद्धान्जलि होगी। इस श्रद्धान्जलि में ग्रामों की भूमिका अहम होगी। गाँधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान दिल्ली में हाथ से मैला उठाने बालों की बस्ती में निवास का फैसला लिया। वह समझते थे कि स्वच्छता के महत्व पर बात करना तब तक निरर्थक है, जब तक सामाजिक अस्पृश्यता के कलंक को चुनौती नहीं दी जाये। वास्तव में स्वच्छता गाँधी के लिए बुनियादी और सामाजिक बदलाव की दृष्टि से अनिवार्य मुद्दा था।

स्वच्छ भारत अभियान के रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती जन जागरूकता, जन भागीदारी, नागरिक कर्तव्यों की चुनौती है। सांसद सदस्य श्री उदित राज ने अपने क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिल्ली के वार्ड 52 की साफ सफाई की स्थिति जानने की कोशिश की तो नगर निगम के अधिकारी वार्ड में तैनात सफाई कर्मचारियों की सूची तक उपलब्ध नहीं करा सके। साथ ही क्षेत्र में ऐसे अनेक सरकारी शौचालय मिले जो रख–रखाव के अभाव में टूटी फूटी हालत में पहुंच गये (राज 2015)। यह हालत गांवों में भी है। पंचायत घरों की बदहाली, स्कूलों को पशु आहतों में परिवर्तित कर लेना, तालाबों पर अवैध कब्जे, गांव के रास्तों एवं गलियों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेना, सार्वजनिक भूमि पर अवैध अधिकार, तथा गांवों में यदा कदा बने शौचालयों की टूटी फूटी स्थिति किसी से छिपी नहीं है।

निष्कर्ष

ग्रामों एक ओर तो व्यक्ति जी भर के मेहनत करता है, उसकी गणना दुनियां के सबसे मेहनती व्यक्तियों में की जाती है वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जो आलसी बनकर बैठे रहते हैं या अनार्थिक कार्यों में लगे रहते हैं। अतः ग्रामीण विकास में एक बडी चुनौती ग्रामीण समाज की इस खाली समय में बैठी रहने वाली जनसंख्या को गतिशील बनाकर उसे ग्राम के विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाये। सभी व्यक्ति जब तक एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का वहन नहीं करते तब तक इस व्यवस्था में सुधार नहीं होने वाला। कोई भी कितने भी बडे या छोटे पद पर हो, वह एक नागरिक भी है और उसे अपने समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।

References

1. Agarwal, O.P. (2014), Smart City ka Matlab, Dainik Jagran, Novemeber 14, Agra
2. Aryendu, Akhilesh (2015), Swakshhata Se Samajik Parivartan: Vikas Ke Raste, Yojana (Hindi), Year 59, Number, 1 January 2015, pp 69-72
3. Census of India (2011), The Registrar General and Census Commissioner of India, New Delhi
4. Gandhi, M.K. (1962), Village Swaraj, Complied by H M Vyas, Navajivan Publishing House: Ahmadabad
5. Kumar, Gaurav (2015), Samajik Mansikata Mein Badlav Se Hi Sambhav Hei Swakshha Bharat, Yojana (Hindi), Year 59, Number, 1 January 2015, pp 61-64
6. Mohanti, B.B. (2009), Development through People's Empowerment: Lessson form Rural Maharashtra, in Barik, Bishnu C. & Sahoo, Umesh C. (ed.), Panchayati Raj Insitutions and Rural Development: Narratives on Inclusion of Excluded, Rawat Publications Jaipur
7. Mahipal (2014), Panchayati Raj Mein Swachha Bharat, Dainik Jagran, November 17, Agra
8. Mattausch, John (2014), Gandhi's Prescription: health and Hygiene in Unfinished Struggle for Swaraj, South Asia Research, Volume 34, Number 2, July 2015
9. Peter, Oakley et al. (1999), Project with People: The Practice of Participation in Rural Development, International Labour Organization
10. Raj, Udai (2015), Swaksha Bharat ki Chunotiyan, Dainik Jagran, Jagram Prakashan, 15 February, 2015, Agra
11. Singh, Kartar (2009), Rural Development-Principles, Policies and Management (III Edition), Sage Publications Indian Pvt. Ltd., New Delhi